



## गेल (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)

### GAIL (India) Limited

(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,  
16 भीकारजी कामा प्लेस  
नई दिल्ली-110066, इंडिया  
GAIL BHAWAN,  
16 BHIKAJIJI CAMA PLACE  
NEW DELHI-110066, INDIA  
फोन/PHONE : +91 11 26182955  
फैक्स/FAX : +91 11 26185941  
ई-मेल/E-mail : info@gail.co.in

ND/GAIL/SECTT/2021

18.08.2021

1. Listing Compliance National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400051 <b>Scrip Code: GAIL-EQ</b>	2. Listing Compliance BSE Limited Floor 1, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400001 <b>Scrip Code: 532155</b>
--	--

**Sub.: Newspaper Publication of Dispatch of Notice of the 37<sup>th</sup> AGM - Regarding**

Dear Sir,

This is in compliance of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

With reference to the subject cited above, please find the attachment.

The above is for your information and records.

Thanking you,  
Yours faithfully,

(A.K. Jha)  
Company Secretary

Encl<sup>1</sup> As above



# अफगानिस्तान से भारतीय स्वदेश लौटे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगान स्थिति पर मंगलवार को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की

एजेंसियां

अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के नियंत्रण के बाद उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि, बैठक में क्या चर्चा हुई इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। इससे पहले, काबुल में भारतीय राजदूत एवं दूतावास के कर्मियों समेत 120 लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान मंगलवार को अफगानिस्तान से भारत पहुंच गया। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बारे में सूत्रों ने कहा कि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला, अफगानिस्तान में भारत के राजदूत आर टंडन सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

इस बीच, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सभी भारतीयों की अफगानिस्तान से सकुशल वापसी को लेकर प्रतिबद्ध है और काबुल हवाईअड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों की बहाली होते ही वहां फंसे अन्य भारतीयों को स्वदेश लाने का प्रबंध किया जाएगा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सुरक्षा हालात के मद्देनजर भारतीय दूतावास के कर्मियों को लेकर एक सैन्य विमान स्वदेश लौट आया। भारतीय वायुसेना का सी-17 विमान राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के पास स्थित हिंडन वायु सेना स्टेशन आने के क्रम में पूर्वाहन करीब सवा ग्यारह बजे गुजरात के जामनगर स्थित वायुसेना स्टेशन पर उतरा था। ऐसी खबरें हैं कि इस विमान से कुछ अन्य भारतीय नागरिक भी लौटे हैं। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने जामनगर में पत्रकारों से कहा कि काबुल में हालात बेहद खराब हैं और वहां फंसे भारतीयों को वाणिज्यिक उड़ान सेवा शुरू होने के बाद वापस लाया जाएगा। टंडन ने कहा कि दूतावास में हमारे 192 कर्म हैं जिन्हें दो चरणों में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तीन दिन के भीतर अफगानिस्तान से वापस लाया गया है। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में दायित्व संभालने वाले टंडन ने कहा कि काबुल में तेजी से बदली स्थिति के बीच दूतावास ने अनेक परेशान भारतीयों की मदद की और उन्हें शरण भी दी।

इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटीनी ब्लिंकन से अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। जयशंकर अमेरिका के चार दिवसीय दौर पर न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने सोमवार देर रात तीन बजे ट्वीट में कहा कि उन्होंने ब्लिंकन के साथ अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत ने काबुल में हवाईअड्डा संचालन बहाल करने की अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया। जयशंकर ने कहा कि वह इस संबंध में अमेरिकी प्रयासों की बहुत सराहना करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि जयशंकर और ब्लिंकन ने अफगानिस्तान संबंधी हालात पर चर्चा की। भारत अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। इसी के मद्देनजर जयशंकर सुरक्षा परिषद के इस सप्ताह दो उच्च स्तरीय अहम कार्यक्रमों की अध्यक्षता के लिए सोमवार को न्यूयॉर्क आए।

इस बीच, भारत ने मंगलवार को अफगान नागरिकों के लिए आपात ई-वीजा जारी करने की घोषणा की। सभी अफगान नागरिक (चाहे वे किसी भी धर्म में आस्था क्यों नहीं रखते हों) ऑनलाइन इस वीजा के आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों पर नई दिल्ली में विचार होगा। भारत ने यह ई-वीजा उन लोगों के लिए जारी किया है जो तालिबान के कब्जे के बाद भारत आना चाहते हैं।



जामनगर स्थित वायुसेना के अड्डे पर अफगानिस्तान से वापस लौटे भारतीयों का स्वागत करते अधिकारी

फोटो-पीटीआई

## काबुल में सरकार गठन पर चर्चा तेज

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां सरकार गठन पर चर्चा तेज हो गई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि भविष्य में वहां तालिबान के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में गैर-तालिबान सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं। इस विषय पर राजधानी काबुल में चर्चा हो रही है। इस बातचीत से जुड़े लोगों ने मंगलवार को नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि कहा कि आगे एक या दो दिन में इस संबंध में कोई ठोस नतीजा निकल सकता है।

वरिष्ठ तालिबान नेता आमिर खान मुत्तकी पहले ही अब्दुल्ला अब्दुल्ला और पूर्व राष्ट्रपति हमिद करजई समेत काबुल के राजनीतिक नेतृत्व के साथ कई दौर की वार्ता कर चुके हैं। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने एक बार देश के वार्ता परिषद की अगुवाई की थी। कम से कम एक दौर की वार्ता शत भर चली। तालिबान के शासन के दौरान शिक्षा मंत्री रहे मुत्तकी ने पिछले सप्ताह के आखिर में राष्ट्रपति अशरफ गनी के राष्ट्रपति भवन से चले जाने से पहले से ही अफगान राजनीतिक नेताओं के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया था। मुत्तकी ने काबुल के तालिबान के कब्जे में

आने से पहले अमेरिका समर्थित धरुं से संपर्क करने का प्रयास किया। यह सरकार में सभी लोगों को शामिल करने की तालिबान की शुरुआती पहल जान पड़ती है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पहले कहा था कि यह एक समावेशी अफगान सरकार होगी।

### आम माफी की घोषणा

इस बीच, तालिबान ने मंगलवार को पूरे अफगानिस्तान में आम माफी की घोषणा की और महिलाओं से उसकी सरकार में शामिल होने का आह्वान किया। तालिबान के प्रतिनिधियों ने लोगों के मन में व्याप्त भय भी दूर करने की कोशिश की। तालिबान के डर से सोमवार को काबुल छोड़कर भागने की कोशिश करते लोगों की वह से स्थानीय हवाईअड्डे पर अफगान-तफरी मच गई थी। इस घटना में कई लोग मारे गए थे। काबुल में उत्पीड़न या लड़ाई की बड़ी घटना की खबर अब तक नहीं आई है। तालिबान द्वारा जेलों पर कब्जा कर केदियों को छोड़ने एवं हथियारों को लूटने की घटना के बाद कई शहरी घरों

में मौजूद हैं, लेकिन भयभीत हैं। कई महिलाओं ने आशंका जताई है कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के दौरान महिलाओं को और अधिकार देने का प्रचलित प्रयोग तालिबान के शासन में कायम नहीं रहेगा।

तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य इनामुल्ला समानगनी ने आम माफी का वादा किया है। यह पहली बार है जब तालिबान की ओर से संघीय स्तर पर शासन को लेकर टिप्पणी की गई है। समानगनी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि आम माफी से उसका क्या अभिप्राय है। हालांकि, अन्य तालिबानी नेताओं ने कहा कि वे उन लोगों से बदला नहीं लेना चाहते हैं जो पूर्ववर्ती सरकार या विदेशों में कार्यरत थे। इस बीच, मंगलवार को नाटो के अफगानिस्तान में वरिष्ठ असेन्य प्रतिनिधि स्टीफेनो पोटेकावो ने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिख रहा है कि हवाईअड्डे की उड़ान पट्टी खाली है और अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तस्वीर में चेन से बनी सुरक्षा दीवार के पीछे सेना के मालवाहक विमान देखे जा सकते हैं।



### पेगासस विवाद

## न्यायालय का केंद्र सरकार को नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने कथित पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच करने की मांग से संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और यह स्पष्ट किया कि वह नहीं चाहता कि सरकार ऐसी किसी बात का खुलासा करे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सुवंत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के पीठ ने यह टिप्पणी सरकार के यह कहने के बाद की कि हलफनामे में सूचना की जानकारी देने से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा है।

पीठ ने कहा कि उसने सोचा था कि सरकार एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करेगी लेकिन इस मामले में सिर्फ सीमित हलफनामा दाखिल किया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 10 दिन बाद इस मामले को सुनेगी और देखेगी कि इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। केंद्र का पक्ष रख रहे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार ने सोमवार को दाखिल हलफनामे में अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था। मेहता ने पीठ को बताया, 'हमारी सुविचारित प्रतिक्रिया वही है जो हमने सम्मानपूर्वक अपने पिछले हलफनामे में दी थी। कृपया इस मामले को हमारे नजरिये से देखें क्योंकि हमारा हलफनामा पर्याप्त है। भारत सरकार देश की सर्वोच्च अदालत के सामने है।' उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि वह सच्ची पहलुओं के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगी और यह समिति शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा, 'छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है' और इस मामले से राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू जुड़ा है। मेहता ने कहा कि यह मामला 'सार्वजनिक बहस का मुद्दा' नहीं हो सकता और विशेषज्ञों की समिति शीर्ष अदालत को रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा, 'यह एक संवेदनशील मामला है जिसे संवेदनशीलता से निपटा जाना चाहिए।' भाषा

## टीके की सबसे अधिक खुराक लगाने का रिकॉर्ड

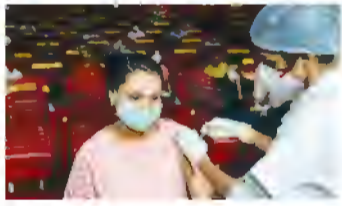
भारत ने 24 घंटे में कोविड-19 टीके की 88.13 लाख से अधिक खुराक दी है जो एक दिन में सबसे अधिक खुराक लगाने का रिकॉर्ड है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, 'भारत ने एक दिन में सबसे अधिक कोविड-19 टीके की खुराक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। कल (बीता हुआ) इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े टीका अभियान के तौर पर दर्ज होगा। बधाई।' मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को सुबह तक मिला अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 62,12,108 टीकाकरण सत्र में अंततः कोविड-19 टीके की 55,47,30,609 खुराक दी गई है। अबतक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सौतों से कोविड-19 टीके की 56.81 करोड़ खुराक खुराका कराई गई है और 1,09,32,960 खुराकों की आपूर्ति प्रक्रियागत है। मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 2.25 करोड़ टीके की खुराक मौजूद है। भाषा

## टीके के पेच से दोबारा बंद हुए मॉल

सुशील मिश्र

कोरोना के मामलों में कमी आने और व्यापारी संगठनों की लगातार मांग को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 15 अगस्त से दुकानों और रेस्तरांओं की समय सीमा बढ़ा दी। साथ ही 130 दिनों के इंतजार के बाद शांति मॉल भी खुल गए लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नए दिशानिर्देश के मुताबिक मॉल में वही कर्मचारी जा सकते हैं जिन्होंने कोरोना टीके की दोनों खुराक ली हैं। इस शर्त को अधिकांश शांति मॉल पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिसके चलते मंगलवार को लगभग सभी मॉल दोबारा बंद हो गए।

शांति मॉल सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और इनफिनिटी मॉल के सीईओ मुकेश कुमार के मुताबिक चार महीने से कारोबार बंद रहने के बाद कुछ



उम्मीद जगी थी लेकिन सरकार द्वारा ऐसी शर्तें लगाई गईं जिन पर व्यावहारिक तौर पर खरा उतरना मुमकिन नहीं है, सभी मॉल दो दिन खुलने के बाद एक बार फिर बंद हो गए हैं। कर्मचारियों के लिए दोनों खुराक जरूरी वाला परिपत्र सोमवार शाम को जारी किया गया। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कि सभी मॉल हर रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। मॉल में आने वाले कर्मचारियों और लोगों को दोनों खुराक का टीकाकरण प्रमाण पत्र और एक वैध फोटो पहचान

पत्र ले जाना होगा। चूंकि 18 साल से कम उम्र की आबादी के लिए टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मॉल के प्रवेश बिंदुओं पर अपनी उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेज दिखाने की जरूरत है। इस बीच प्रशासन के एक निर्णय ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी। प्रशासन ने माल डिब्बों में सामान के परिवहन की अनुमति दे दी है। इससे टेम्पो के मंहगे भाड़े से छुटकारा मिलागा। रेलवे लोकल में सफर में और भी छूट देने के संकेत देने लगा है। कोरोना टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को 15 अगस्त से लोकल में सफर की अनुमति दी मिल गई है। लोकल में भीड़ नियंत्रित रहती है तो जल्द ही एक खुराक ले चुके लोगों को भी लोकल में सफर की अनुमति मिल सकती है।

## स्वास्थ्य क्षेत्र में उतरेंगे विनोद के दासरी

शाइन जैकब

रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्यकारी के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद विनोद के दासरी ने सस्ती स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास के अपने शौक पर काम करने के लिए पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हालांकि इस बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि उनका भविष्य का शौक क्या है? केवल मीडिया को बताया गया था कि यह 'गैर-लाभकारी' उद्यम होगा। दासरी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'यह अभी शुरुआती दौर में है। मैं बहुत से वर्षों तक कारोबारी अगुआ रहने के बाद समाज को कुछ लौटाना चाहता हूँ। मेरी योजना अपनी पत्नी सरिता द्वारा स्थापित स्वास्थ्य उद्यम पर आगे बढ़ने की है, जो खुद एक डॉक्टर हैं।' वह रॉयल एनफील्ड से जुड़ने से पहले एक अन्य प्रमुख वाहन विनिर्माता कंपनी अशोक लीलैंड में वर्ष 2011 से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी थे। दासरी ने 4 अगस्त को चेन्नई के नुंगमबक्कम में उनके परिवार के स्वामित्व वाले 40 बेड के

मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल विजय गंगा स्पेशियलिटी केयर लिमिटेड (वीजीएससी) का उद्घाटन किया था। दासरी ने कहा कि यह अस्पताल अगले 15 दिन के भीतर चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'इसकी सफलता का आधार पर हम आगे और अस्पताल खोलने का फैसला लेंगे। हमने इस अस्पताल पर करीब 75 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हमने इस नए उद्यम पर जितना निवेश किया है, वह कंपनी जगत में एक मामूली राशि हो सकती है।' वीएसजीसी की स्थापना डॉ. सरिता ने वर्ष 2009 में की थी और इसे वर्ष 2013 में मायलापुर में एक छोटे क्लिनिक के रूप में शुरू किया गया था। नया अस्पताल व्यापक सेवाएं मुहैया कराएगा, जिनमें रोकथाम एवं स्वास्थ्य, वेस्क्यूलर सेवाएं, नेफ्रोलॉजी सेवाएं, यूरोलॉजी सेवाएं, सामान्य स्पेशियलिटी, अस्पताल देखभाल, जांच और उपचार सेवाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा, 'भारत में हर पांच में से एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। हर तीन में से एक को उच्च-रक्तचाप की समस्या है और मेरी पत्नी इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। ऐसे



में हमने सोचा है कि हम कुछ मिलकर बनाने के लिए कैसे उनके और मेरे कौशल का लाभ ले सकते हैं।' डॉ. सरिता हुबली स्थित कर्नाटक मेडिकल कॉलेज से स्नातक हैं और उन्होंने अमेरिका के ओहायो के आल्टमैन हॉस्पिटल से इंटरनल मेडिसिन में विशेषज्ञता और क्लीवलैंड क्लिनिक फाउंडेशन (सीसीएफ) से नेफ्रोलॉजी में अति विशेषज्ञता हासिल की है। यह दंपती वीजीएससी की डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट प्रशिक्षण अकादमी का भी विस्तार करने की योजना बना रहा है, जिसे ट्रेनलाइफ के नाम से भी जाता है

विनोद के दासरी

ताकि छात्रों, नर्सिंग अटेंडेंट और मौजूदा डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्टों के कौशल को विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा, 'लोगों को प्रशिक्षण और उनका करियर बनाने में मदद क्यों नहीं दी जानी चाहिए। यह उपक्रम का हिस्सा होगा। हम उन सभी कौशलों पर विचार करेंगे, जिनकी इस खंड में जरूरत होती है।' जब उनसे गैर-लाभकारी मॉडल के बारे में पूछा गया तो दासरी ने कहा कि जो लोग इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, उनका खर्च एक

न्यास उठाएगा। दासरी का मानना है कि वह अपने बेटे संजय दासरी के कृषि कारोबार उद्यम वेकूल फूड्स की सफलता को समाज को कुछ लौटाने के अपने फैसले के पीछे की एक वजह मानते हैं। चेन्नई की वेकूल फूड्स तेजी से बढ़ रही कृषि-वाणिज्य कंपनियों में से एक है, जो खाद्य विकास एवं वितरण पर केंद्रित है। कंपनी का राजस्व चालू वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये पर पहुंचने का आसार है। जब दासरी से कारपोरेट दुनिया छोड़ने के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी दार्शनिक की तरह जवाब दिया।

उन्होंने कहा, 'मेरा जुनून या उपहार निवेशक उद्यम खड़े करना है। जीवन का अर्थ आपका उपहार ढूँढना है और जीवन का उद्देश्य इसे लौटाना है। मैं इसे कैसे लौटा सकता हूँ।' मैं इसे किसी एनजीओ को नहीं दे सकता। इसका बेहतर तरीका यह है कि ऐसा कुछ शुरू किया जाए, जो बढ़ता रहे ताकि रोजगार सहित समाज को कुछ लौटाना जा सके।' रॉयल एनफील्ड में दासरी की जगह सीईओ बी गोविंदराज लेंगे, जो कंपनी में मुख्य परिचालन अधिकारी हैं।

**गेल (इंडिया) लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उपक्रम)

**गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेरधारकों हेतु सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की 37वीं (सैतिसवीं) वार्षिक आम सभा (एजीएम) **गुर्वा, दिनांक 09 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / ऑनलाइन (ऑनलाइन) माध्यम (ओवीपी) से आयोजित की जाएगी। इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और निमित्य बोर्ड (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम, 2016 (प्रासंगिक प्रावधानों) की एमसीआईडी के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 06 मई, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 15 जनवरी, 2021 (एमसीएम परिपत्र) तथा भारतीय प्रतिभूति और निमित्य बोर्ड ('सेबी') के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/पी/सीआईआर/2021/602 दिनांक 23 जुलाई, 2021 ("सेबी परिपत्र") के साथ पथा जाए जिनमें वीसी/ओवीपीएम के माध्यम से वार्षिक आम सभा के आयोजन की प्रक्रियाओं और तरीकों के बारे में बताया गया है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार 37वीं एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी डिफॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डी. पी) अथवा आर. एंड टी. ए. के पास पंजीकृत है। उन्हीं कंपनी की वेबसाइट ([www.gallonline.com](http://www.gallonline.com)), स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) तथा सेंट्रल डिफॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट ([www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)) पर भी होस्ट किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग करके 37वीं वार्षिक आम सभा की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है। रिमोट-ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कंपनी द्वारा डिफॉजिटरी सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इंडिया) लिमिटेड को तैनात किया गया है। रिमोट-ई-वोटिंग की अवधि **सितंबर, दिनांक 05 सितंबर, 2021 (ग्राह्य 9:00 बजे) (ग्राह्य 9:00 बजे) से ग्राह्य 09:00 बजे तक** रहेगी और **गुर्वा, दिनांक 09 सितंबर, 2021 (ग्राह्य 5:00 बजे) (ग्राह्य 5:00 बजे)** को समाप्त होगी। उसके पश्चात रिमोट-ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के उपरान्त उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

वे व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों में सदस्य के रूप में अथवा डिफॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में निर्दिष्ट तिथि अर्थात् **गुर्वा, दिनांक 02 सितंबर, 2021** को पंजीकृत है, केवल वही रिमोट-ई-मतदान की सुविधा का लाभ लेने अथवा एजीएम में भाग लेने या एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होगा।

रिमोट-ई-वोटिंग द्वारा वोटिंग करने वाले सदस्य वीसी/ओवीपीएम के माध्यम से वार्षिक आम सभा में भाग ले सकते हैं लेकिन वे मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे। किसी संकल्प पर ई-वोटिंग द्वारा एक बार मतदान करने के पश्चात प्रत्येक सदस्य को उसे परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। रिमोट-ई-वोटिंग सुविधा <https://www.evotingindia.com> लिंक पर उपलब्ध है। वीसी/ओवीपीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे शेरधारक जो रिमोट-ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाल सके और अस्थायी ऐसा करना जिन्हें वंचित नहीं है, केवल वही एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम सभा के नोटिस के रिमोट-ई-वोटिंग भाग के अनुरोधों पर ध्यान दें। यदि आपके पास ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम एवं ई-वोटिंग में भाग लेने से संबंधित कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप [www.evotingindia.com](mailto:www.evotingindia.com) के हेल्प डेस्क अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) को ईमेल लिख सकते हैं [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) अथवा 022-23058738 और 022-23058542 / 43 पर संपर्क कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप में हमारे आर. एंड टी. ए. से [admin@mcscrregistrars.com](mailto:admin@mcscrregistrars.com) या भी आज्ञा दला, महाराष्ट्र, एमसीएस एस्टीए से फोन नं. 91-11-44106149-62 (नता: एमसीएस शेर ट्रेंसफर एजेंट लिमिटेड, युनिट: गेल (इंडिया) लिमिटेड, प्रथम तल, एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1, नई दिल्ली-110020) से संपर्क करें।

यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल/एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत है तो विद्यमान लॉग इन आईडी और पासवर्ड ई-वोटिंग हेतु प्रयुक्त होगा। जो व्यक्ति कंपनी द्वारा नोटिस जारी होने के पश्चात शेर अधिगृहीत किए हैं और कंपनी के सदस्य बने हैं तथा कट ऑफ तारीख को शेर धारण करते हैं, वे लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड हासिल करने के लिए [shareholders@gall.co.in](mailto:shareholders@gall.co.in) अथवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर अपने शेरधारिता के विवरण सहित अनुरोध भेज सकते हैं।

अपने सदस्यों की बेहतर सेवा हेतु कंपनी को सक्षम बनाने के लिए अनुरोध है कि जो सदस्य नेशनल ऑटोमेटेड विलियर्स हाउस (NACH) सुविधा का लाभ लेने के लिए इच्छुक हैं अथवा किसी भी लाभांश राशि का प्रत्यक्ष क्रेडिट प्राप्त करने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिफॉजिटरी (DP) (यदि शेरधारक को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा जाता है) या आर एंड टी ए / कंपनी (यदि शेरधारकों को भौतिक मोड में रखा जाता है) के साथ बैंक विवरण अपडेट करें।

इसके अतिरिक्त भौतिक रूप में शेरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी भौतिक शेरधारिता को डिफेंडरिजेशन करें। सभी परिपत्र सं-सेबी/एचओ/एमसीआईआर/सीआईआर/पी/2020/236 दिनांक 2 दिसम्बर, 2020 को ध्यान में रखते हुए कंपनी/आरएफडीए द्वारा भौतिक रूप में शेरधारकों के हस्ताक्षर के लिए अनुरोध के स्थानांतरण या संचरण के मामले को छोड़कर पर कार्यवाई नहीं की जाएगी।

सदस्य (सी) जिन्होंने अभी तक अपने डिविडेंड वॉरंट(टी) को नुस्त्या नहीं है वेEPF को ट्रान्सफर करने की नियत तारीख से कम से कम 3 सप्ताह पहले डिमांड ड्राफ्ट (टी) जारी करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आरएफडीए/कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य (सी) विस्तृत संदर्भ के लिए कंपनी की वेबसाइट पर 'निवेशक जोन' अनुभाग पर जा सकते हैं। सदस्य (ओ) को अपने अनुरोध/शिकायत दर्ज करने की सुविधा के लिए, यदि कोई है, तो आरएफडीए और कंपनी की निर्दिष्ट ई-मेल आईडी [admin@mcscrregistrars.com](mailto:admin@mcscrregistrars.com) या [shareholders@gall.co.in](mailto:shareholders@gall.co.in) पर है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के संदर्भ में कंपनी 09 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से एजीएम के सामान्य तद वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का एकराफा लाइव वेबकास्ट प्रदान कर रही है। उक्त को आप गेल की वेबसाइट ([www.gallonline.com](http://www.gallonline.com)) पर एक्सेस कर सकते हैं।

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 18.08.2021  
ई-मेल: [shareholders@gall.co.in](mailto:shareholders@gall.co.in)  
फोन: 011-26182955  
फैक्स: 011-26185941

सीआईएन: L4200DL1984G0I018976

कृते गेल (इंडिया) लिमिटेड  
हस्ता/—  
(ए के झा)  
कंपनी सचिव

[www.gallonline.com](http://www.gallonline.com) | पंजी: कर्नाट: 16, भीकानी कामा चनेक, बाराक, पुष्प, नई दिल्ली-110066. Follow us on